International Journal of Multidisciplinary Education and Research
www.multidisciplinaryjournals.in
ISSN: 2455-4588
Received: 22-08-2023, Accepted: 10-09-2023, Published: 25-09-2023
Volume 8, Issue 3, 2023, Page No. 69-74

उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊँ मण्डल की वर्तमान औद्योगिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ० किरन कुमार पन्त[1], सोनिया विलासराय[2]
[1] असिस्टेन्ट प्रोफेसर (वाणिज्य विभाग), राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चम्पावत, उत्तराखंड, भारत
[2] शोध छात्रा (वाणिज्य विषय), पी.एन.जी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर, नैनीतालं, उत्तराखंड, भारत

सारांश
किसी देश अथवा राज्य के आर्थिक विकास में औद्योगीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत का नव निर्मित राज्य उत्तराखण्ड अपनी प्राकृतिक व मानवीय सम्पदा के लिए विख्यात है और इसी सम्पदा से धनी कुमाऊँ मण्डल अपने संसाधनों के उचित दोहन के माध्यम से औद्योगिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। कुमाऊँ मण्डल के मैदानी जनपद ऊधम सिंह नगर में अभूतपूर्व औद्योगिक विकास की स्थिति देखने को मिलती है तो वहीं पर्वतीय जनपदों में अभी भी औद्योगिक विकास की गति मंद है। प्रस्तुत शोध पत्र में कुमाऊँ मण्डल के सभी जनपदों की वर्तमान औद्योगिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है एवं प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सुझाव प्रस्तुत किये गए हैं।

मूल शब्दः उत्तराखण्ड, कुमाऊँ मण्डल, औद्योगिक विकास, औद्योगीकरण, औद्योगिक स्थिति

आज के समय में औद्योगिक विकास के बिना किसी भी देश की प्रगति एवं विकास की कल्पना मात्र नहीं की जा सकती क्योंकि औद्योगीकरण के द्वारा ही, उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का उचित दोहन सम्भव होता है। औद्योगिक विकास के द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विकास के साथ–साथ सांस्कृतिक विकास को बल मिलता है अतः औद्योगिक विकास तब तक अपूर्ण माना जाता है जब तक उसका सन्तुलित विकास न हो। सन्तुलित औद्योगिक विकास का तात्पर्य उद्योगों के केंद्रीयकरण को रोककर उद्योगों के विकेंद्रीयकरण से है। विकेंद्रीयकरण के अन्तर्गत उद्योगों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में, सन्तुलित विकास प्राप्त करने के लिए स्थापित किया जाता है। औद्योगीकरण किसी देश की सम्पन्नता व प्रगति का आधार मात्र नहीं बल्कि उस देश के आर्थिक विकास का मापदण्ड भी होता है तथा किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास में औद्योगीकरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है इससे किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का उपयोग होता है और साथ ही साथ विभिन्न उद्योग धन्धों के विकास से उस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होते हैं फलस्वरूप बेरोजगारी की समस्या का निवारण होता है अतः यहाँ ये कहना उचित होगा कि वर्तमान समय की प्रमुख समस्या बेरोजगारी का समाधान ढूँढने में औद्योगीकरण का महत्वपूर्ण योगदान है।

उत्तराँचल भारत का 27वाँ राज्य 9 नवम्बर सन् 2000 को अस्तित्व में आया परन्तु स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, 1 जनवरी 2007 को उत्तराँचल नाम को परिवर्तित करके उत्तराखण्ड रख दिया गया। उत्तराखण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 53,484 वर्ग किलेमीटर है जो कि देश के क्षेत्रफल का 1. 63 प्रतिशत है। इसका पूर्व से पश्चिम तक विस्तार लगभग 358 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 320 किलोमीटर है।[1] क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 18वाँ राज्य है।[2] सम्पूर्ण राज्य गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डल नामक दो मण्डलों में विभक्त है। गढ़वाल मण्डल में सात जिले सम्मिलित हैं जो कि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं चमोली हैं। कुमाऊँ मण्डल में छः जिले सम्मिलित हैं जो कि ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चम्पावत हैं।

नवगठित राज्य प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के दृष्टिकोण से एक सम्पन्न राज्य है। प्राकृतिक संसाधनों में वन तथा खनिज पर्याप्त मात्रा में हैं, प्राचीन काल से ही मनुष्य और वनस्पति का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। उत्तराखण्ड में भी वनसम्पदा का विशाल भण्डार है। राज्य के सभी जिलों में कुल 24,305 वर्ग किलोमीटर में वन सम्पदा का विस्तार है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 45.44 प्रतिशत भाग वनाच्छादित क्षेत्र है।[3] यहाँ के वनों में साल, शीशम, चीड़, तून, देवदार, खेर, हाल्दू, बाँस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं, इन वृक्षों से ही लीसा, कत्था, झूला कोमल काष्ठ जैसे पदार्थ प्राप्त होते हैं जो अन्य अनेक उद्योगों का आधार हैं। वनों में जड़ी–बूटियों के पर्याप्त भण्डार भी हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाई जा सकती हैं। खनिजों में मैग्नेसाइट, लाइमस्टोन, सोपस्टोन, जिप्सम तथा पत्थर की स्लेटें मुख्य हैं। साहसी क्षमता के अभाव के कारण यहाँ के निवासियों में उद्योगों की स्थापना के लिए कोई विशेष रूचि नहीं रही है। औद्योगीकरण के अभाव में उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण विदोहन न हो पाने से यह राज्य स्वतंत्रता प्राप्ति के 76 वर्षों के बाद भी आर्थिक एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है।

1. साहित्य की समीक्षा

अपने शोध पत्र को शुरू करने से पूर्व उत्तराखण्ड में औद्योगिक विकास की स्थिति को जानने के लिए सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन किया गया ताकि उत्तराखण्ड में औद्योगिक विकास की स्थिति से सम्बन्धित ज्ञान में स्पष्टता एवं वृद्धि हो सके। प्रस्तुत शोध पत्र में निम्नलिखित साहित्य का अध्ययन किया गया है–

सिंह सारिका (2003)[4] – भारत में उद्योगों का विकास कुछ थोड़े से राज्यों में ही अधिक हुआ, जबकि अन्य राज्यों में उद्योगों के स्थानीयकरण की गति अत्यंत मंद रही। इस विषय परिस्थिति का परिणाम यह हुआ है कि कुछ राज्यों को इन लाभों के बहुत थोड़े भाग को प्राप्त करके ही संतोष करना पड़ा है। औद्योगिक विकास एवं अल्प विकास के इस सह– अस्तित्व की परिणति अनेक विषमताओं के रूप में प्रकट हुई। औद्योगिक विकास एवं पिछड़ेपन का सह– अस्तित्व देश के उन राज्यों में भी विद्यमान है जिनमें उद्योगों का केंद्रीयकरण अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक हुआ है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्य भी पिछड़ेपन का शिकार हैं।

गुप्ता, गोपाल दास (2007)[5] – जनसंख्या बाहुल्य एवं निम्न आय स्तर वाले देशों के औद्योगिक विकास में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विशेष महत्व होता है। यह उद्योग बड़े पैमाने पर तत्काल रोजगार के अवसर सुलभ कराने में समर्थ होते हैं। पूँजी तथा उत्पादन साधनों को प्रभावशाली ढंग से गति देने तथा राष्ट्रीय आय के अपेक्षाकृत अधिक न्यायपूर्ण वितरण का आश्वासन देते हैं। सीधे वृहत स्तरीय औद्योगिक विकास की नीति को अपनाने के प्रयास में एक अल्प विकसित देश की अर्थव्यवस्था अनेक विषमताओं का शिकार हो सकती है।

जोशी, दुर्गादत्त (1992)[6] – दुर्गा दत्त जोशी जी द्वारा किए शोध, नैनीताल जनपद में लघु एवं कुटीर उद्योगों के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष से ज्ञात होता है कि लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास के लिए बनाई गई औद्योगिक नीति का सकारात्मक प्रभाव इन उद्योगों पर पड़ा है। छठी पंचवर्षीय योजना से विनियोजन को बढ़ाया गया है तथा पिछले 20 वर्षों से वास्तविक औद्योगीकरण परिलक्षित हो सका है।

सोनी, मृदुल (2019)[7] – लेखिका ने अपने शोध ग्रंथ, उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास में वित्तीय संस्थानों के योगदान पर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है। इनके शोध प्रबंध से ज्ञात होता है कि सरकार के अनेक प्रयासों के बावजूद भी लघु उद्योग प्रगति नहीं कर पा रहे हैं जिसका एक मुख्य कारण वित्तीय संस्थानों द्वारा लघु उद्योगों की अवहेलना करके वृहद उद्योगों को अपेक्षाकृत अधिक ऋण प्रदान करना है।

राणा नारायण सिंह (1980)[8] – कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल में वर्ष 1980 में अपने शोध प्रबंध ा में श्री नारायण सिंह राणा जी ने पंचवर्षीय योजनाओं में कुमाऊँ मण्डल के औद्योगिक विकास का अध्ययन किया है। इसके अन्तर्गत उन्होंने पाया कि कुमाऊँ मण्डल का पर्वतीय क्षेत्र औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है। सरकार द्वारा बनाई गई औद्योगिक नीति में पिछड़े क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने के बाद भी अभी तक पिछड़े क्षेत्रों में केंद्र सरकार की किसी भी परियोजना को कार्यरत नहीं किया गया है। लघु एवं कुटीर उद्योगों को भी हर संभव सहायता प्रदान करने के बारे में कहा गया लेकिन मण्डल में अभी भी हस्तकला के प्राचीन उद्योग लुप्त हो रहे हैं।

2. अध्ययन के उद्देश्य

- उत्तराखण्ड के कुमाऊँ मण्डल की वर्तमान औद्योगिक स्थिति को स्पष्ट करना।
- कुमाऊँ मण्डल में औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

3. अध्ययन पद्धति

यह शोध आलेख मुख्य रूप से विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति पर आधारित है। वर्तमान अध्ययन उत्तराखण्ड के कुमाऊँ मण्डल की वर्तमान औद्योगिक स्थिति के विविध पक्षों की विश्लेषण से सम्बन्धित है अतः यह शोध आलेख पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। इस अध्ययन के मूल स्रोत उद्योग निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण निदेशालय, जिला उद्योग केंद्रों तथा अध्ययन से सम्बन्धित विभिन्न वेबसाइट आदि हैं।

4. कुमाऊँ मण्डल का सामान्य परिचय

हिमालय पर्वत के ऊँचे शिखरों के दक्षिणी ढलान पर मानव के रहने योग्य निचली श्रेणियाँ व विस्तृत पहाड़ियाँ हैं। कुमाऊँ मण्डल का अक्षांशीय विस्तार 28°–31′ से 30°–49′ अक्षांश उत्तर तक तथा 77°–43′ देशांतर पूर्व से 81°–31′ देशांतर पूर्व तक है। कुमाऊँ मण्डल का भौगोलिक क्षेत्रफल 21,035 वर्ग किलोमीटर है जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 39.33 प्रतिशत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मण्डल के अन्य जिलों की तुलना में पिथौरागढ़ अपेक्षाकृत बड़ा जिला है जबकि चम्पावत सबसे छोटा जिला है। कुमाऊँ के पूर्व में काली नदी द्वारा भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा बनी हुई है और उत्तर में हिमालय की जल विभाजक रेखा कुमाऊँ को तिब्बत से अलग करती है, इस प्रकार कुमाऊँ मण्डल के दो भाग भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे हुए हैं।

कुमाऊँ मण्डल की कुल जनसंख्या 42,28,998 है। जो कि राज्य की जनसंख्या का 41.93 प्रतिशत है। जनसंख्या की दृष्टि से ऊधम सिंह नगर सबसे बड़ा जिला है जबकि चम्पावत सबसे छोटा जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार मण्डल में 1000 हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 978 है एवं साक्षरता 78.52 प्रतिशत है।[9]

किसी भी क्षेत्र की प्रगति एवं स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर का सूचक उस क्षेत्र का औद्योगिक आकार होता है। उत्तराखण्ड में औद्योगीकरण को यहाँ के पर्वतीय भागों की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, दुर्गमता, कठोर जलवायु व उद्यमिता विकास की भावना एवं मानवीय संसाधनों के पलायन आदि तत्वों ने बाधित किया है। उत्तराखण्ड के गठन से पूर्व यह क्षेत्र उद्योग विहीन क्षेत्र के रूप में जाना जाता था और गठन के पश्चात भी आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास के प्रमुख आर्थिक स्रोत के रूप में नहीं जाना जाता है। राज्य में अवस्थापना सुविधाओं की कमी होने से यहाँ पर निवेशकों की कोई रुचि नहीं थी जिस कारण औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त निवेश के अवसर नहीं उपलब्ध हो पाते थे।

राज्य में वितरित औद्योगिक परिस्थितियों के कारण राज्य के गठन से पहले प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध होने के बावजूद यह क्षेत्र भारी तथा मध्यम उद्योगों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था जबकि कुटीर उद्योगों का विकास अपेक्षाकृत अधिक हुआ था। राज्य के गठन के समय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को मिलाकर यहाँ पर कुल 14,163 उद्योग स्थापित थे जबकि वृहद उद्योगों की संख्या केवल 41 थी। राज्य में स्थापित उद्योगों से 67,600 लोगों को रोजगार मिला हुआ था। राज्य के गठन के पश्चात् औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम 8 जुलाई 2001 को औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। वर्तमान समय में उत्तराखण्ड, भारत सरकार द्वारा दिए गए विशेष औद्योगिक पैकेज व रियायतों के कारण निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बन गया है। बजाज टाटा हीरो हौंडा हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड नेस्ले ब्रिटानिया आईटीसी बिरला टायर्स टीवीएस मोटर अशोक लेलैंड और कई अन्य उद्योग कुमाऊँ मण्डल में स्थापित हैं।

5. कुमाऊँ मण्डल की वर्तमान औद्योगिक स्थितिः

उत्तराखण्ड की अनुकूल औद्योगिक नीतियों तथा उदार कर लाभों के कारण पूँजी निवेश में हुई भारी वृद्धि के कारण यह राज्य भारत में सबसे तीव्र गति से विकास करने वाले राज्यों में से एक है। यहाँ अनेक हिल स्टेशनों, तीर्थ स्थलों, वन्यजीव पार्कों व ट्रेकिंग मार्ग होने के कारण उत्तराखण्ड एक आकर्षक पर्यटन स्थल बन चुका है।

राज्य में प्रचुर वन सम्पदा होने के कारण वनों पर आधारित उद्योगों के विकास की सम्भावनाऐं प्रबल हैं। यहाँ कुटीर उद्योगों के विकास की भी उत्तम सम्भावनाऐं हैं । राज्य में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, वन आधारित उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, चाय उद्योग, रसायन उद्योग, प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित उद्योग, औषधि निर्माण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, शराब निर्माण उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि प्रमुख बड़े उद्योग स्थापित हैं।

राज्य में हस्तशिल्प उद्योग, हथकरघा उद्योग, भेड़ पालन उद्योग, ऊन आधारित उद्योग, काष्ठ आधारित उद्योग, खादी व ग्रामोद्योग, मोम आधारित उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, नमकीन निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, मसाला निर्माण उद्योग, पापड़ निर्माण उद्योग, साबुन निर्माण उद्योग, कपड़ों की छपाई का उद्योग, चूड़ी निर्माण उद्योग, दोना पत्तल निर्माण उद्योग, आइसक्रीम उद्योग, जड़ी–बूटी उद्योग, दियासलाई उद्योग, जूता चप्पल निर्माण उद्योग, दाल और धान की छिलाई उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन उद्योग, मुर्गी पालन उद्योग आदि ग्रामीण व कुटीर उद्योग स्थापित है।

5.1 कुमाऊँ मण्डल में स्थापित कुल औद्योगिक इकाईयों में पूँजी निवेश एवं सृजित रोजगार की जिलेवार स्थितिः

कुमाऊँ मण्डल में कुल 22,277 औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित हैं। इन औद्योगिक इकाईयों में कुल पूँजी निवेश 6676ण88 करोड़ रू० किया गया है। इन इकाइयों के माध्यम से 2,19,462 रोजगार सृजित हुए हैं।[10] उत्तराखण्ड में स्थापित कुल औद्योगिक इकाईयों में पूँजी निवेश एवं सृजित रोजगार की सितम्बर, 2023 तक की जिलेवार स्थिति को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है–

सारणी संख्या – 1

जिले का नाम	स्थापित औद्योगिक इकाईयों की संख्या	पूँजी निवेश (करोड़ में)	सृजित रोजगार
अल्मोड़ा	3720	455ण40	11928
बागेश्वर	2028	290ण97	95216
चम्पावत	1445	53ण90	4363
नैनीताल	3960	293ण50	15977
पिथौरागढ़	2368	83ण35	6418
ऊधम सिंह नगर	8756	5499ण76	85560
कुल योग	22277	6676ण88	219462

स्त्रोत : उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित

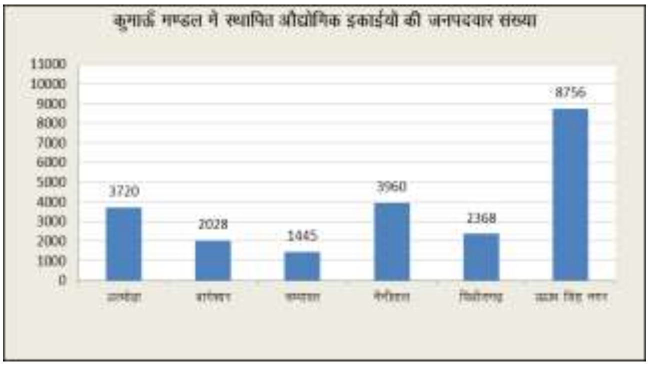

ग्राफ संख्या– 1

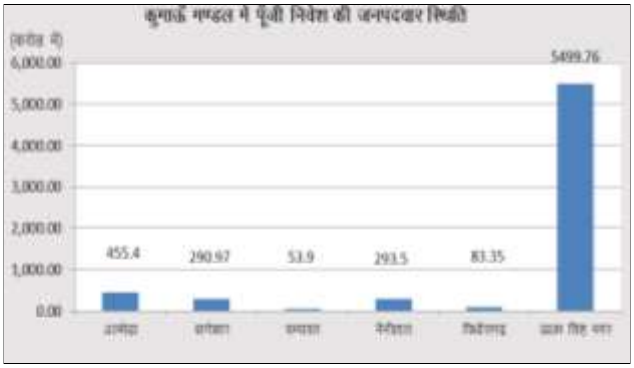

ग्राफ संख्या 2

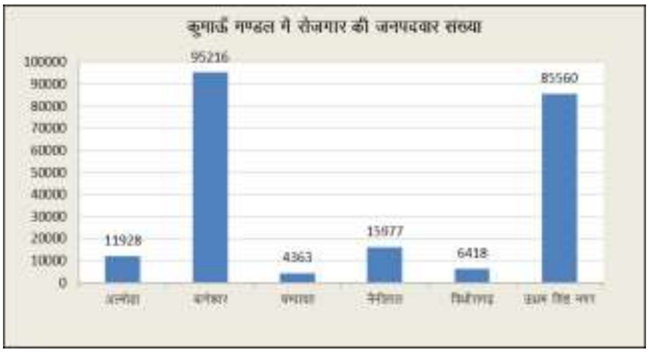

ग्राफ संख्या 3

5.2 कुमाऊँ मण्डल में स्थापित कुल औद्योगिक इकाईयों की स्थितिः

कुमाऊँ मण्डल में स्थापित कुल औद्योगिक इकाईयों की सितम्बर, 2023 तक की स्थिति को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है –

सारणी संख्या 2: कुमाऊँ मण्डल में स्थापित कुल औद्योगिक इकाईयों की स्थिति

क्रियाकलाप के अनुसार	पैमाने के अनुसार				योग
	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	वृहद्	
निर्माण क्षेत्र	15277	1257	74	97	16705
सेवा क्षेत्र	5371	177	23	1	5572
कुल योग	20648	1434	97	98	22277

स्त्रोत : उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित

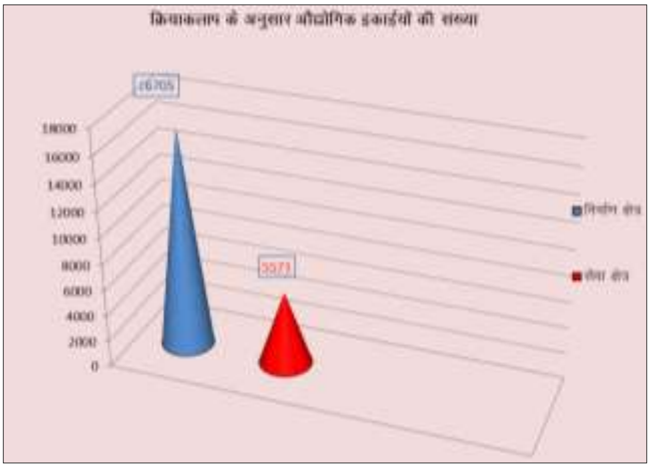

पाई चार्ट संख्या – 1

व्याख्या – सारणी संख्या 2 में कुमाऊँ मण्डल में स्थापित कुल औद्योगिक इकाईयों की स्थिति को दर्शाया गया है। कुमाऊँ मण्डल में 22277 कुल औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित हैं जिनमें निर्माण क्षेत्र की इकाईयों की संख्या 16,705 एवं सेवा क्षेत्र की इकाईयों की संख्या 5572 है। मण्डल में वृहद् इकाईयों की संख्या 98 है जिनमें से 97 इकाईयाँ निर्माण क्षेत्र की हैं व 1 इकाई सेवा क्षेत्र की है। मण्डल में मध्यम इकाईयों की संख्या 98 है जिनमें निर्माण व सेवा क्षेत्र की इकाईयाँ क्रमशः 74, 23 हैं। मण्डल में लघु इकाईयों की संख्या 1434 है जिनमें निर्माण व सेवा क्षेत्र की इकाईयाँ क्रमशः 1257, 177 हैं। मण्डल में सूक्ष्म इकाईयों की संख्या 20648 है जिनमें निर्माण व सेवा क्षेत्र की इकाईयाँ क्रमशः 15277, 5371 हैं।

5.3 कुमाऊँ मण्डल में स्थापित औद्योगिक इकाईयों की जनपदवार स्थिति

विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य उत्तराखण्ड में औद्योगिक विकास 22 साल बाद भी एक चुनौती बना हुआ है। हालाँकि इस अवधि के दौरान सरकार ने इसके लिए अनेक प्रयास भी किए हैं परन्तु पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास अभी भी संभव नहीं हो पा रहा है। राज्य के गठन के पश्चात् वर्ष 2002–03 में तत्कालीन केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज दिया गया। इस पैकेज के सकारात्मक प्रभाव को राज्य के ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून जिलों में औद्योगिक विकास के रूप में आज भी देखा जा रहा है।

- **ऊधम सिंह नगर में स्थापित औद्योगिक इकाईयों की स्थिति**

ऊधम सिंह नगर जनपद की सितम्बर, 2023 तक की औद्योगिक स्थिति को निम्नलिखित सारणी के माध्यम से दर्शाया गया है –

सारणी संख्या 3: ऊधम सिंह नगर में स्थापित औद्योगिक इकाईयों की स्थिति

क्रियाकलाप के अनुसार	पैमाने के अनुसार				योग
	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	वृहद्	
निर्माण क्षेत्र	5151	1103	48	94	6396
सेवा क्षेत्र	2265	91	4	.	2360
कुल योग	7416	1194	52	94	8756

स्त्रोत : उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित

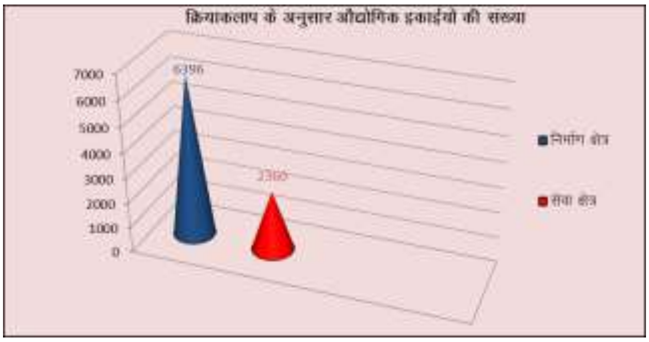

पाई चार्ट संख्या – 2

व्याख्या – सारणी संख्या 3 में ऊधम सिंह नगर में स्थापित कुल औद्योगिक इकाईयों की स्थिति को दर्शाया गया है। ऊधम सिंह नगर जनपद में कुल औद्योगिक इकाईयों की संख्या 8756 है, जिनमें निर्माण क्षेत्र की इकाईयों की संख्या 6396 एवं सेवा क्षेत्र की इकाईयों की संख्या 2360 है। जनपद में कुल वृहद् इकाईयों की संख्या 94 है जो कि निर्माण क्षेत्र से हैं । जनपद में कुल मध्यम इकाईयों की संख्या 52 है जिनमें निर्माण व सेवा क्षेत्र की इकाईयाँ क्रमशः 48, 4 हैं। जनपद में कुल लघु इकाईयों की संख्या 1194 है जिनमें निर्माण व सेवा क्षेत्र की इकाईयाँ क्रमशः 1103, 91 हैं। जनपद में कुल सूक्ष्म इकाइयों की संख्या 7416 है जिनमें निर्माण व सेवा क्षेत्र की इकाईयाँ क्रमशः 5151, 2265 हैं।

- **नैनीताल में स्थापित औद्योगिक इकाईयों की स्थिति**

नैनीताल जनपद की सितम्बर, 2023 तक की औद्योगिक स्थिति को निम्नलिखित सारणी के माध्यम से दर्शाया गया है –

सारणी संख्या – 4: नैनीताल में स्थापित औद्योगिक इकाईयों की स्थिति

क्रियाकलाप के अनुसार	पैमाने के अनुसार				योग
	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	वृहद्	
निर्माण क्षेत्र	3392	73	4	3	3472
सेवा क्षेत्र	448	30	9	1	488
कुल योग	3840	103	13	4	3960

स्त्रोत : उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित

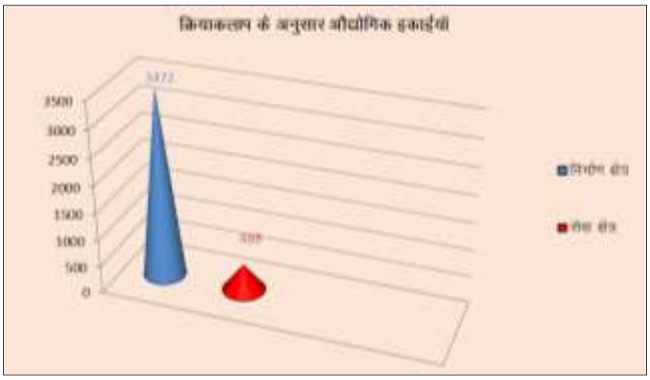

पाई चार्ट संख्या – 3

व्याख्या – सारणी संख्या 4 में जनपद नैनीताल में स्थापित कुल औद्योगिक इकाईयों की स्थिति को दर्शाया गया है। नैनीताल जनपद में कुल औद्योगिक इकाइयों की संख्या 3960 है, जिनमें निर्माण क्षेत्र की इकाइयों की संख्या 3472 एवं सेवा क्षेत्र की इकाइयों की संख्या 488 है। जनपद में कुल वृहद् इकाइयों की संख्या 4 है जिनमें निर्माण व सेवा क्षेत्र की इकाइयाँ क्रमशः 3, 1 हैं। जनपद में कुल मध्यम इकाइयों की संख्या 13 है जिनमें निर्माण व सेवा क्षेत्र की इकाइयाँ क्रमशः 4, 9 हैं। जनपद में कुल लघु इकाइयों की संख्या 103 है जिनमें निर्माण व सेवा क्षेत्र की इकाइयाँ क्रमशः 73, 30 हैं। जनपद में कुल सूक्ष्म इकाइयों की संख्या 3840 है जिनमें निर्माण व सेवा क्षेत्र की इकाइयाँ क्रमशः 3392, 448 हैं।

- **अल्मोड़ा में स्थापित औद्योगिक इकाईयों की स्थिति**

अल्मोड़ा जनपद की सितम्बर, 2023 तक की औद्योगिक स्थिति को निम्नलिखित सारणी के माध्यम से दर्शाया गया है –

सारणी संख्या 5: अल्मोड़ा में स्थापित औद्योगिक इकाईयों की स्थिति

क्रियाकलाप के अनुसार	पैमाने के अनुसार				योग
	सूक्ष्म	**लघु**	**मध्यम**	**वृहद्**	
निर्माण क्षेत्र	3274	75	22	.	3371
सेवा क्षेत्र	303	37	9	.	349
कुल योग	3577	112	31	.	3720

स्त्रोत : उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित

पाई चार्ट संख्या – 4

व्याख्या – सारणी संख्या 5 में जनपद अल्मोड़ा में स्थापित कुल औद्योगिक इकाईयों की स्थिति को दर्शाया गया है । अल्मोड़ा जनपद में कुल औद्योगिक इकाईयों की संख्या 3720 है, जिनमें निर्माण क्षेत्र की इकाईयों की संख्या 3371 एवं सेवा क्षेत्र की इकाईयों की संख्या 349 है। जनपद में कुल मध्यम इकाईयों की संख्या 31 है जिनमें निर्माण व सेवा क्षेत्र की इकाईयाँ क्रमशः 22, 9 हैं । जनपद में कुल लघु इकाईयों की संख्या 112 है जिनमें

निर्माण व सेवा क्षेत्र की इकाईयाँ क्रमशः 75, 37 हैं। जनपद में कुल सूक्ष्म इकाईयों की संख्या 3577 है जिनमें निर्माण व सेवा क्षेत्र की इकाईयाँ क्रमशः 3274, 303 हैं ।

- **बागेश्वर में स्थापित औद्योगिक इकाईयों की स्थिति**

बागेश्वर जनपद की सितम्बर, 2023 तक की औद्योगिक स्थिति को निम्नलिखित सारणी के माध्यम से दर्शाया गया है –

सारणी संख्या 6: बागेश्वर में स्थापित औद्योगिक इकाईयों की स्थिति

क्रियाकलाप के अनुसार	पैमाने के अनुसार				योग
	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	वृहद्	
निर्माण क्षेत्र	1051	.	.	.	1051
सेवा क्षेत्र	976	1	.	.	977
कुल योग	2027	1	.	.	2028

स्त्रोत : उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित

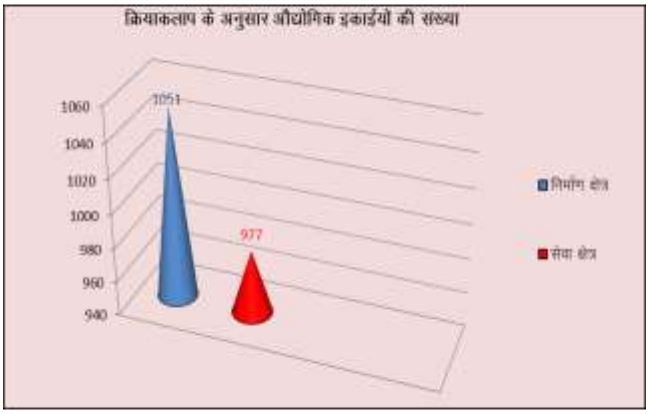

पाई चार्ट संख्या 5

व्याख्या – सारणी संख्या 6 में जनपद बागेश्वर में स्थापित कुल औद्योगिक इकाईयों की स्थिति को दर्शाया गया है । बागेश्वर जनपद में कुल औद्योगिक इकाईयों की संख्या 2028 है, जिनमें निर्माण क्षेत्र की इकाईयों की संख्या 1051 एवं सेवा क्षेत्र की इकाईयों की संख्या 977 है। जनपद में कुल लघु इकाईयों की संख्या 1 है जो कि सेवा क्षेत्र से है । जनपद में कुल सूक्ष्म इकाईयों की संख्या 2027 है जिनमें निर्माण व सेवा क्षेत्र की इकाईयाँ क्रमशः 1051, 976 हैं।

- **चम्पावत में स्थापित औद्योगिक इकाईयों की स्थिति**

चम्पावत जनपद की सितम्बर, 2023 तक की औद्योगिक स्थिति को निम्नलिखित सारणी के माध्यम से दर्शाया गया है –

सारणी संख्या 7: चम्पावत में स्थापित औद्योगिक इकाईयों की स्थिति

क्रियाकलाप के अनुसार	पैमाने के अनुसार				योग
	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	वृहद्	
निर्माण क्षेत्र	695	.	.	.	695
सेवा क्षेत्र	750	.	.	.	750
कुल योग	1445	.	.	.	1445

स्त्रोत : उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित

पाई चार्ट संख्या 6

व्याख्या – सारणी संख्या 7 में जनपद चम्पावत में स्थापित कुल औद्योगिक इकाईयों की स्थिति को दर्शाया गया है। चम्पावत जनपद में केवल सूक्ष्म इकाईयाँ ही स्थापित हैं जिनकी संख्या 1445 है, जिनमें निर्माण क्षेत्र की इकाईयों की संख्या 695 एवं सेवा क्षेत्र की इकाईयों की संख्या 750 है।

- **पिथौरागढ़ में स्थापित औद्योगिक इकाईयों की स्थिति**

पिथौरागढ़ जनपद की सितम्बर, 2023 तक की औद्योगिक स्थिति को निम्नलिखित सारणी के माध्यम से दर्शाया गया है –

सारणी संख्या 8: पिथौरागढ़ में स्थापित औद्योगिक इकाईयों की स्थिति

क्रियाकलाप के अनुसार	पैमाने के अनुसार				योग
	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	वृहद्	
निर्माण क्षेत्र	1714	6	.	.	1720
सेवा क्षेत्र	629	18	1	.	648
कुल योग	2343	24	1	.	2368

स्त्रोत : उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित

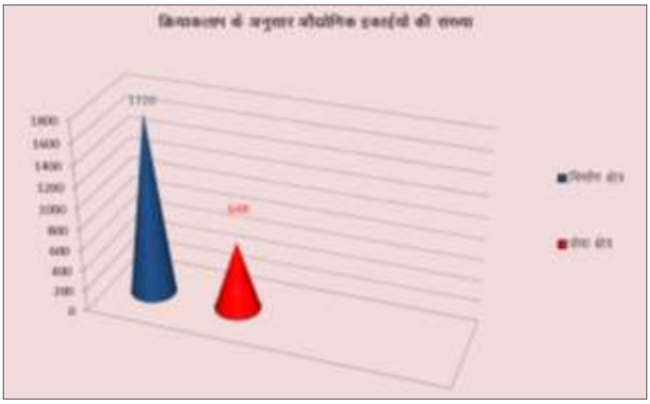

पाई चार्ट संख्या – 7

व्याख्या – सारणी संख्या 8 में जनपद पिथौरागढ़ में स्थापित कुल औद्योगिक इकाईयों की स्थिति को दर्शाया गया है । पिथौरागढ़ जनपद में कुल औद्योगिक इकाईयों की संख्या 2368 है, जिनमें निर्माण क्षेत्र की इकाईयों की संख्या 1720 एवं सेवा क्षेत्र की इकाईयों की संख्या 648 है। जनपद में कुल मध्यम इकाईयों की संख्या 1 है जो कि सेवा क्षेत्र से है । जनपद में कुल लघु इकाईयों की संख्या 24 है जिनमें निर्माण व सेवा क्षेत्र की इकाईयाँ क्रमशः 6, 18 हैं । जनपद में कुल सूक्ष्म इकाईयों की संख्या 2343 है जिनमें निर्माण व सेवा क्षेत्र की इकाईयाँ क्रमशः 1714, 629 हैं।

6. निष्कर्ष एवं सुझाव

राज्य के गठन के पश्चात् औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम 8 जुलाई 2001 को औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। वर्तमान समय में उत्तराखण्ड, भारत सरकार द्वारा दिए गए विशेष औद्योगिक पैकेज व रियायतों के कारण निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बन गया है। उत्तराखण्ड की अनुकूल औद्योगिक नीतियों तथा उदार कर लाभों के कारण पूँजी निवेश में हुई भारी वृद्धि के कारण यह राज्य भारत में सबसे तीव्र गति से विकास करने वाले राज्यों में से एक है। राज्य में प्रचुर वन सम्पदा होने के कारण वनों पर आधारित उद्योगों के विकास की संभावनाऐं प्रबल हैं। यहाँ कुटीर उद्योगों के विकास की भी उत्तम सम्भावनाऐं हैं।

विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य उत्तराखण्ड में औद्योगिक विकास 22 साल बाद भी एक चुनौती बना हुआ है। हालाँकि इस अवधि के दौरान सरकार ने इसके लिए अनेक प्रयास भी किए हैं परन्तु पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास अभी भी सम्भव नहीं हो पा रहा है। राज्य के गठन के पश्चात् वर्ष 2002–03 में तत्कालीन केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज दिया गया। इस पैकेज का सकारात्मक प्रभाव केवल ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून जनपद में ही देखा जा रहा है।

उत्तराखण्ड में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों जल, वन, खनिज, बागवानी, जड़ी–बूटी एवं मानवीय संसाधनों का नियोजित एवं तर्कपूर्ण विदोहन किया जाए तो राज्य को आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के पथ पर अग्रसर किया जा सकता है और राज्य के गठन के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। यहाँ कृषि भूमि सीमित तथा स्थलाकृति विषम होने के कारण यहाँ कृषि में यंत्रीकरण एवं अन्य सुधार कार्यों का क्षेत्र सीमित है अतः औद्योगीकरण के अन्तर्गत विशेषतः लघु एवं कुटीर उद्योग धन्धे लगाकर यहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर युवा वर्ग के पलायन को रोका जा सकता है।

यहाँ पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रयोग सम्भव हो सकता है यदि कृषि में अन्य फसलें उगाने की बजाय फलोत्पादन तथा सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाए। आर्थिक विकास होने से लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी जिससे सामाजिक विकास होगा। इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि औद्योगीकरण द्वारा इस क्षेत्र की निर्धनता, बेरोजगारी और पिछड़ेपन की समस्याओं को दूर किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची

1. सिंह, वीरेन्द्र, (2009), ''भारत के राज्य, उत्तराखण्ड, विस्तृत अध्ययन'', अरिहन्त पब्लिकेशन्स, पृष्ठ संख्या 9।
2. सिंह, महेन्द्र रावत, ''उत्तराखण्ड समग्र अध्ययन'', अरिहन्त पब्लिकेशन्स, पृष्ठ संख्या 61।
3. *उत्तराखण्ड की 17वीं वन रिपोर्ट, 2021।*
4. सिंह सारिका, (2003), ''रोल एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया'', पीएच० डी० शोध प्रबन्ध, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश, पृष्ठ संख्या 364।
5. गुप्ता, गोपाल दास, (2007), ''उत्तर प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में राजकीय योगदान का एक मूल्यांकन'', पीएच० डी० शोध प्रबन्ध, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश, पृष्ठ संख्या 254।
6. जोशी, दुर्गादत्त, (1992),''नैनीताल जनपद में लघु एवं कुटीर उद्योगों का अध्ययन'', पीएच० डी० शोध प्रबन्ध, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
7. सोनी, मृदुल, (2019), ''उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास में वित्तीय संस्थानों का योगदान एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन'', अप्रकाशित पीएचडी शोध प्रबंध, लखनऊ विश्वविद्यालय, पृष्ठ संख्या 237।
8. राणा, नारायण सिंह, (1980), ''पंचवर्षीय योजनाओं में कुमाऊँ मण्डल का औद्योगिक विकास'', पीएच० डी० शोध प्रबन्ध, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
9. *उत्तराखण्ड जनगणना रिपोर्ट, 2011।*
10. *उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड* ।